SHODH SAMAGAM

ISSN : 2581-6918 (Online), 2582-1792 (PRINT)

छत्तीसगढ़ में कृषि विकास योजनाएँ तथा उसके प्रभाव का अध्ययन

आशीष दूबे, वाणिज्य विभाग,
मनोज मिश्रा, प्राचार्य,
विवेकानंद महाविद्यालय, रायपुर, छत्तीसगढ़, भारत

ORIGINAL ARTICLE

Corresponding Author's :
आशीष दूबे, वाणिज्य विभाग,
मनोज मिश्रा, प्राचार्य,
विवेकानंद महाविद्यालय, रायपुर, छत्तीसगढ़, भारत

shodhsamagam1@gmail.com

Received on : 13/03/2020
Revised on : -----
Accepted on : 21/03/2020
Plagiarism : 07% on 14/03/2020

Plagiarism Checker X Originality Report
Similarity Found: 7%

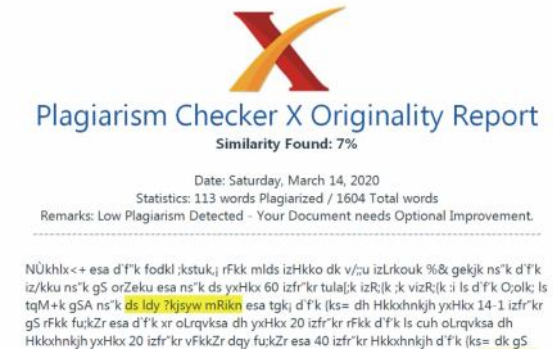

Date: Saturday, March 14, 2020
Statistics: 113 words Plagiarized / 1604 Total words
Remarks: Low Plagiarism Detected - Your Document needs Optional Improvement.

NÙkhlx<+ esa d`f"k fodkl ;kstuk,¡ rFkk mlds izHkko dk v/;;u izLrkouk %& gekjk ns"k d`f'k iz/kku ns"k gS orZeku esa ns"k ds yxHkx 60 izfr"kr tula[;k izR;{k ;k vizR;{k :i ls d`f'k O;olk; ls tqM+k gSA ns"k ds ldy ?kjsyw mRikn esa tgk¡ d`f'k {ks= dh Hkkxhnkjh yxHkx 14-1 izfr"kr gS rFkk fu;kZr esa d`f'k xr oLrqvksa dh yxHkx 20 izfr"kr rFkk d`f'k ls cuh oLrqvksa dh Hkkxhnkjh yxHkx 20 izfr"kr vFkkZr dqy fu;kZr esa 40 izfr"kr Hkkxhnkjh d`f'k {ks= dk gS

प्रस्तावना :–

हमारा देश कृषि प्रधान देश है वर्तमान में देश के लगभग 60 प्रतिशत जनसंख्या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि व्यवसाय से जुड़ा है। देश के सकल घरेलू उत्पाद में जहाँ कृषि क्षेत्र की भागीदारी लगभग 14.1 प्रतिशत है तथा निर्यात में कृषि गत वस्तुओं की लगभग 20 प्रतिशत तथा कृषि से बनी वस्तुओं की भागीदारी लगभग 20 प्रतिशत अर्थात कुल निर्यात में 40 प्रतिशत भागीदारी कृषि क्षेत्र का है देश की जनता की कृषि पर निर्भरता तथा उनके लिए कृषि के महत्व को इस बात से समझा जा सकता है कि जनसाधरण के उपभोग बजट में कृषि उत्पाद की भागीदारी लगभग 85 प्रतिशत है। उपरोक्त विश्लेषण हमारे देश की कृषि पर निर्भरता को स्पष्ट करता है तृतीय विश्व के राष्ट्रों में अग्रणी होने के बाद भी हमारा आज भी कृषि प्रधान देश हैं छत्तीसगढ़ राज्य की लगभग 80 प्रतिशत जनता कृषि या कृषि पर आधारित उद्योगों पर निर्भर है प्रदेश के लगभग 37.46 लाख कृषक परिवारों में से 75 प्रतिशत लघु एवं सीमान्त कृषक की श्रेणी में आते है जो कृषि के महत्व को और अधिक बढ़ा देते है।

मुख्य शब्द :–

तृतीय विश्व, कृषि, लघु एवं सीमांत कृषक।

अध्ययन का उद्देश्य :–

अध्ययन का उद्देश्य प्रदेश के कृषि क्षेत्र के वास्तविकता का अध्ययन करना है तथा प्रदेश सरकार द्वारा संचालित विभिन्न कृषि गत विकास योजनाओं पर प्रकाश डालना है।

परिकल्पनाएँ :–

अध्ययन के प्रमुख परिकल्पनाओं मे

निम्नलिखित शामिल है :–

1. छत्तीसगढ़ का कृषि क्षेत्र अत्यन्त पिछड़ा है।
2. प्रदेश में कृषि व्यवसाय के लिए संचालित योजनाओं का लाभ कृषकों को नहीं मिल पाता हैं।
3. प्रदेश में संगठित कृषि उपज मंडी का अभाव हैं।

अध्ययन की सीमाएँ :–

अध्ययन मुख्यतः शासन द्वारा उपलब्ध की गयी योजनाओं से संबंधित साहित्यों पर आधारित है परिणामों के अध्ययन के लिए सीमित क्षेत्रों के अध्ययन को शामिल किया गया है जिनके आधार पर निष्कर्ष तक पहुँचा गया है।

वर्तमान में छत्तीसगढ़ कृषि पर पूर्णतः निर्भर है राज्य में कृषि तकनीक परंपरागत एवं मुख्यतः वर्षा पर निर्भर हैं प्रदेश के कुल कृषि क्षेत्र के लगभग 30 प्रतिशत क्षेत्र में सिचांई की सुविधा उपलब्ध है, तथा शेष कृषि क्षेत्र प्राकृतिक वर्षा पर निर्भर हैं प्रदेश के 62 प्रतिशत सिंचित क्षेत्र जलाशयों तथा नहरों के माध्यम से सिंचित है। राज्य के अधिकांश भूमि से वर्ष में एक बार ही फसल ली जा सकती है। प्रति हेक्टेयर अल्प उत्पादन प्रदेश के कृषि की गंभीर समस्या है जिसके प्रमुख कारणों में कृषि की परंपरागत तकनिक उन्नत बीजों की अनुपलब्धता बीज उपचार सुविधाओं का अभाव कीटनाशकों का अभाव उर्वरकों का अभाव आदि शामिल है। सरकार द्वारा प्रदेश में कृषि के विकास के लिए कृषि विश्वविघालय तथा कृषि विभाग के माध्यम से अनेक योजनाओं का संचालन कर रही है किन्तु इन योजनाओं का उचित लाभ कृषकों को प्राप्त नही हो रहा है। प्रदेश के कृषकों की वित्तीय स्थिति भी कृषि पिछडेपन का प्रमुख कारण है इस स्थिति से निपटने के लिए सरकार द्वारा कृषि ऋण कृषि बीमा उर्वरक सब्सिडी आदि योजनओं का संचालन किया जा रहा है जिसका लाभ कृषकों आंशिक ही प्राप्त हो रहा है। जिसका प्रमुख कारण योजनाओं का कृषकों तक न पहुँच पाना कृषि प्रकार्य का परंपरागत स्वरूप अशिक्षा परिवहन के साधनों का अभाव है।

सरकार द्वारा प्रदेश में कृषि के विकास के लिए अनेक योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। जिसके अन्तर्गत राज्य में स्थापित 4.50 लाख सिंचाई नलकूप के रिचार्जिग एवं वर्षा जल ग्रहण के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के माध्यम से स्थानीय नालों एवं छोटी नदियों में जगह–जगह भूमिगत बंधारा निर्मित किये जायेगें जिससे भू–जलस्तर में वृद्धि होगी एवं आगामी जाँच वर्षो में ऐसी 10 हजार संरचानाएँ निर्मित की जाएगी। प्रदेश के छोटे बड़े नाले में श्रृंखला बद्ध तरीके से चेक डेम निर्मित किये जाऐगे। प्रतिवर्श 700 किमी लम्बाई में 700–725 चेकडेम को निर्माण राज्य पोषित योजना प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना रेनफेड एरिया डेव्हलपमेंट एवं राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के माध्यम से किया जाएगा जिस पर अनुमानित वार्षिक लागत 70 करोड़ रूपये की होगी। आगामी पांच वर्षो में 3500 किमी के उपचार द्वारा 45500 हेक्टर क्षेत्र में उद्वहन सिंचाई तथा इससे लगे हुए 35 हजार हेक्टयर क्षेत्र में नलकुपों के माध्यम से सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी जाएगी। कृषकों के खेतों में सिंचाई क्षमता में वृद्धि के लिए डबरी का निर्माण किया जाएगा। आगामी पांच वर्षो में सिंचाई विभाग द्वारा निर्मित 495 एनीकट, स्टापडेम के किनारों पर विद्युत लाईन विस्तार द्वारा 44 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में उद्वहन सिंचाई को बढ़ावा दिया जाएगा। सिंचाई सुविधा को अधिक प्रभावी बनाने तथा विकास के लिए 3 लाख 60 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में स्प्रिंकलर सेट अनुदान पर उपलबध कराये जाऐंगे।

प्रदेश में कृषि के आधुनिकीकरण के लिए कृषि के साथ साथ उद्यानिकी कृषि वानिकी मुर्गीपालन, पशुपालन को भी कृषि कार्य के साथ सम्मिलित किया जा रहा है। जिससे अन्तर्गत कृषि भूमि के मृदा का परीक्षण कर मिट्टी के गुण के अनुसार उर्वरक उपलब्ध कराने की योजना का संचालन किया जा रहा है। प्रदेश में धान के अतिरिक्त अन्य कृषि उत्पादों के लिए प्रसंस्करण उद्योगों की अत्यधिक कमी है इस कमी को दूर करने के लिए अनेक योजनाओं का संचालन किया जा रहा है कृषि उत्पादों की विपणन व्यवस्था

को सुदृढ़ बनाने के लिए कृषि उत्पादों के गुणों के आधार पर उनकी पहचान के लिए ब्राण्डिंग किया जा रहा है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत छोटी कृषि उत्पाद प्रसंस्करण इकाई की स्थापना हेतु अनुदान उपलब्ध कराने की योजना है। अनुदान द्वारा लघु दाल प्रसंस्करण इकाईयों की स्थापना के लिए विशेष प्रयास किया जा रहा है, ताकि अरहर उत्पादन कृषक दाल के प्रत्यक्ष विक्रय द्वारा अपेक्षाकृत अधि ाक लाभ अर्जित कर सके। राजनांदगांव, कबीरधाम तथा बेमेतरा जिले में सोयाबीन से तेल के उत्पादन इकाई की स्थापना के लिए निजी निवेशकर्ताओं को प्रोत्साहित करने की योजना है। आगामी पांच वर्षो में 100 कृषक समुहों के माध्यम से लघु पोहा, मुरमुरा मिल की स्थापना की योजना है जिनके लिए वित्तीय सहायता एवं अनुदान राष्ट्रीय कृषि विकास योजना एवं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। राष्ट्रीय स्तर के मेले एवं प्रदर्शनियों में प्रदेश के कृषि उत्पादों को प्रदर्शित करने की योजना है जिसके माध्यम से प्रदेश के कृषि उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराया जा सके। राज्य की सभी कृषि उपज मण्डियों को ई–प्लेटफार्म से जोड़ने की येाजना है जिसके माध्यम से कृषकों को कृषि उत्पादों का उचित मूल्य दिलाया जा सके। कृषि उत्पाद में वृद्धि तथा गुण सुधार के लिए जैविक खाद उपलब्ध कराने हेतु भी विस्तृत योजना तैयार किया गया है।

प्रदेश के कृषकों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए अनेक आर्थिक सहायता योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। कृषकों को वर्तमान में शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर अल्पकालीक कृषि ऋण प्रदेश में उपलब्ध कराया जा रहा है जिससे प्रदेश के लगभग 10 लाख कृषक लाभान्वित हो रहे है। वर्ष 2015–16 में 2879 करोड़ रूपये का ऋण वितरण किया गया था जो अगले पांच वर्षो में बढ़ाकर 5772 करोड़ रूपये करने का लक्ष्य रखा गया हैं वर्तमान में राज्य शासन की ब्याज राहत योजना में लगभग 150 करोड़ रूपये का व्यय भार आ रहा है, जो वर्ष 2021–22 तक बढ़कर 300 करोड़ रूपये हो जाने की संभावना है तथा इस योजना से प्रदेश के लगभग 15 लाख किसान लाभान्वित होंगे। वर्तमान में लगभग 10 करोड़ रूपये का मध्यकालीन एवं दीर्घकालीन ऋण का वितरण सहकारी बैंकों के माध्यम से प्रदेश के कृषकों को किया जा रहा है। मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन ऋणों में ब्याज दर 12 प्रतिशत से 13 प्रतिशत होने के कारण इन ऋणों के प्रति कृषकों का उत्साह कम है अतः 4 प्रतिशत दर से ऋण किसानों को उपलब्ध कराने के लिए ब्याज राहत योजना कृषि विभाग के माध्यम से शासन को प्रस्तुत की गयी। वर्ष 2015–16 में संयुक्त देयता समूहों एवं स्व–सहायता समुहों को 26.21 करोड़ रूपये का ऋण वितरित किया गया है जिसे आगामी पांच वर्षो में बढ़कर 67.35 करोड़ करने की योजना हैं उपरोक्त विश्लेषण स्पष्ट करते है कि प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश में कृषि विकास के लिए अनेक योजनाओं का संचालन किया जा रहा है किन्तु इसका लाभ सम्पूर्ण ग्रामीण क्षेत्रों में समान रूप से पड़ रहा है यह स्पष्ट नहीं है। सिचांई की सुविध ाएं सामान्यतः छत्तीसगढ़ के मैदानी इलाकों तक ही सीमित है तथा प्रदेश के अन्य कृषि क्षेत्रों की सिंचाई मानसून पर ही निर्भर है। प्रदेश के अधिकांश कृषक छोटे या सीमान्त कृषक है जिनकी आर्थिक स्थिति अत्यधिक खराब है जिसका प्रमुख कारण प्रदेश का कमजोर कृषि विपणन व्यवस्था है। उपरोक्त तथ्य प्रथम परिकल्पना की सत्यता को प्रदर्शित करते है शासन द्वारा उक्त कृषकों की समस्याओं के समाधान के लिए लगातार प्रयास किया जाता रहा है, किन्तु अशिक्षा, जागरूकता का अभाव आर्थिक असमानता एवं समस्याओं के कारण इन योजनाओं का लाभ सभी कृषक वर्गो को समान रूप से नहीं पहुँच पाता अध्ययन से यह भी स्पष्ट हुआ की प्रदेश की कृषि व्यवस्था में भूमिहीन कृषकों का भी एक वर्ग है जिसके संबंध सरकार की योजनाओं का अभाव है प्रदेश का किसी भी विकास विभाग भूमिहीन कृषकों के अध्ययन स्थिति, सामाजिक व्यवस्था आर्थिक स्थिति के संबंध में उचित जानकारी उपलब्ध नहीं हैं। प्रदेश में कृषकों के सर्वागिण विकास के लिए कृषि क्षेत्र की प्रत्येक समस्याओं का समाधान आवश्यक है अतः उपरोक्त विश्लेषण द्वितीय परिकल्पना के सत्यता को स्पष्ट करते है। प्रदेश में कृषि विपणन की स्थिति भी संतोषजनक नहीं माना जा सकता सरकार द्वारा जिन कृषि उत्पादों का क्रय समर्थन मूल्य पर किया जाता है सामान्यतः कृषक उन्हीं उत्पादों का उचित मूल्य प्राप्त कर पाते है शेष उत्पादों का वे उचित मूल्य प्राप्त

नहीं कर पाते जिसका दीर्घकालिक प्रभाव इन कृषकों की आर्थिक स्थितियों पर पड़ता है। प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में कृषक मंडी अवश्य है किन्तु इन मण्डियों के कार्यकलापों में एकरूपता तथा समन्वय का अभाव है। सभी शासन की योजनाएँ सभी क्षेत्रों पर समान रूप से नहीं पहुँच पाती हैं।

निष्कर्ष :–

अतः स्पष्ट है कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में प्रदेश की कृषि व्यवस्था संतोषजनक नहीं है, इनमें व्यापक सुधार की आवश्यकता हैं। प्रदेश में कृषि का आर्थिक महत्व महत्वपूर्ण होने के बाद भी प्रशासन द्वारा कृषिगत समस्याओ के समाधान के लिए आवश्यक कार्यो का संपादन नहीं किया गया जिसके कारण कृषि क्षेत्रों में विकास अत्यधिक प्रभावित हुआ। कृषि उत्पादों के संरक्षण संवर्धन एवं प्रसंसकरण के लिए भी शासन द्वारा संचालित योजनाएँ संतोषजनक नहीं है। कृषि विपणन समस्या भी प्रदेश के कृषको को भी अत्यधिक प्रभावित कर रही है, जिसके लिए उपर्यक्त कदम उठाने की आवश्यकता है।

संदर्भ सूची :–

1. *भारतीय अर्थव्यवस्था – रूद्रदत्त एवं सुंदरम्।*
2. *मनोरमा ईयर बुक – 2017।*
3. *भारतीय अर्थव्यवस्था अवलोकन – रवीन्द्र भक्कड़।*
4. *उपकार छत्तीसगढ़ वृद्ध संदर्भ – संजय त्रिपाठी।*
5. *दैनिक समाचार पत्र।*

****